

**Series ONS**

**SET-4**

कोड नं.  
Code No. **40**

रोल नं.  
Roll No. 

--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 24 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 30 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains 24 printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 30 questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

**विधिक अध्ययन**  
**LEGAL STUDIES**

निर्धारित समय : 3 घण्टे  
Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 100  
Maximum Marks : 100

### **सामान्य निर्देश :**

- (i) इस प्रश्न-पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं।
- (ii) सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य हैं।
- (iii) प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है।
- (iv) प्रश्न संख्या 9 से 14 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इनमें से प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों से अधिक न हो।
- (v) प्रश्न संख्या 15 से 20 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। इनमें से प्रत्येक का उत्तर 100 शब्दों से अधिक न हो।
- (vi) प्रश्न संख्या 21 से 24 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इनमें से प्रत्येक का उत्तर 150 शब्दों से अधिक न हो।
- (vii) प्रश्न संख्या 25 से 30 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। इनमें से प्रत्येक का उत्तर 200 शब्दों से अधिक न हो।

### **General Instructions :**

- (i) There are 30 questions in all.
- (ii) All the questions are compulsory.
- (iii) Questions number 1 to 8 are multiple choice questions carrying 1 mark each.
- (iv) Questions number 9 to 14 are short answer questions carrying 2 marks each. Answer to each of these should not exceed 50 words.
- (v) Questions number 15 to 20 are short answer questions carrying 4 marks each. Answer to each of these should not exceed 100 words.
- (vi) Questions number 21 to 24 are long answer questions carrying 5 marks each. Answer to each of these should not exceed 150 words.
- (vii) Questions number 25 to 30 are long answer questions carrying 6 marks each. Answer to each of these should not exceed 200 words.

1. भारतीय संसद के द्वारा एक संविधान संशोधन पारित किया गया जिसने भारतीय संविधान के खंड III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संक्षिप्त कर दिया। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त संशोधन को \_\_\_\_\_ शक्ति का उपयोग करते हुए रद्द कर दिया। 1

(क) लोकस स्टैंडी

(ख) न्यायिक पुनर्विलोकन

(ग) जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लेटिगेशन)

(घ) याचिका

A constitutional amendment was passed by the Indian Parliament which abridged rights conferred in Part III of the Indian Constitution. The Supreme Court of India invalidated the said amendment by using the power of :

(a) Locus Standi

(b) Judicial Review

(c) Public Interest Litigation

(d) Writs

2. 32 वर्ष के श्री निखिल को एक केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. 2012 में, एम.डी.यू. से एल.एल.एम 2014 में किया है और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में पी. एच.डी कर रहा है। 1

विधि में सहायक प्राध्यापक पद के लिए विश्वविद्यालय द्वारा रखे गए पात्रता मानदंड थे :

- उम्मीदवार की उम्र 30-35 वर्ष होनी चाहिए
- मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से एल.एल.बी / एल.एल.एम. में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से यू.जी.सी. नेट(विधि) परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए या विधि में पी.एच.डी. होना चाहिए।

दूसरे अभ्यर्थी श्री रूपेश जो साक्षात्कार में सम्मिलित हुआ था, उसने उक्त नियुक्ति को हाइकोर्ट में चुनौती दी है और रिट याचिका दायर की है। उक्त स्थिति में कौनसी रिट लागू होगी ?

(क) हैबियस कॉर्पस

(ख) मैन्डेमस

(ग) को वारंटो

(घ) सर्टियोरारी

Mr. Nikhil aged 32 years, was appointed as Assistant Professor in Law in a Central Government University. He has completed LL.B. from Delhi University in the year 2012 and LL.M. (Masters in Law) from M.D.U. University in the year 2014. Presently, he is pursuing PhD in Law from Delhi University.

The eligibility criteria as laid down by the University for the post of Assistant Professor in law, was :

- Candidate must be of 30 - 35 years old, and
- Should have passed LL.B./LL.M. from a recognized Indian University
- Should have cleared UGC NET (Law) exam or have completed PhD in Law from a recognized Indian University

Another Candidate, Mr. Rupesh who appeared for an interview conducted for the above post challenged the above said appointment of Mr. Nikhil and moved the High Court and invoked the writ jurisdiction.

Which writ would be applicable in the above situation ?

- (a) Writ of Habeas Corpus
- (b) Writ of Mandamus
- (c) Writ of Quo Warranto
- (d) Writ of Certiorari

3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत \_\_\_\_\_ को संधियों को लागू करने का अधिकार है। 1

(क) भारत का राष्ट्रपति और भारत का संसद

(ख) संघ सरकार और राज्य सरकार

(ग) संसद और संघ सरकार

(घ) राज्य सरकार और भारत का राष्ट्रपति

Under Article 253 of the Indian Constitution \_\_\_\_\_ have the power to implement treaties.

(a) President and Parliament of India

(b) Union Government and State Government

(c) Parliament and Union Government

(d) State Government and President of India

4. जिला कानूनी सेवा अधिकरण डी.एल.एस.ए. (DLSA) में शामिल हैं : 1

(क) अध्यक्ष के रूप में जिला जज और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त अन्य सदस्य

(ख) अध्यक्ष के रूप में जिला जज तथा राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त अन्य सदस्य

(ग) अध्यक्ष के रूप में जिला जज और भारत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा राज्य सरकार और मुख्य न्यायाधीश के हाई कोर्ट के परामर्श से नियुक्त अन्य सदस्य

(घ) अध्यक्ष के रूप में जिला जज तथा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त अन्य सदस्य

District Legal Services Authority (DLSA) consists of :

- (a) The District Judge as Chairman, and other members nominated by the Chief Justice of High Court in consultation with State Government.
- (b) The District Judge as Chairman, and other members nominated by the State Government in Consultation with Chief Justice of High Court.
- (c) The District Judge as Chairman, and other members nominated by the Chief Justice of India in consultation with State Government and Chief Justice of High Court.
- (d) The District Judge as Chairman, and other members nominated by the Chief Justice of High Court in consultation with Chief Justice of India.

5. ट्रिस्टन ब्रिटेन का नागरिक है, उसने वहाँ की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में बी.ए. पूरा किया है, वह एल.एल.बी करना चाहता है। ट्रिस्टन को निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होगा ? 1

(क) ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लीगल प्रैक्टिसेज कोर्स (GDLPC)

(ख) ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ कोर्स (GDL)

(ग) ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स (GDPTC)

(घ) ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोफेशनल इक्जामिनेशन (GDPE)

Tristan is a citizen of United Kingdom. He has completed B.A. in Psychology from recognized University of United Kingdom. He wants to pass LL.B. Tristan is required to enrol himself in which of the following course ?

- (a) Graduate Diploma in Legal Practice Course (GDLPC)
- (b) Graduate Diploma in Law Course (GDL)
- (c) Graduate Diploma in Professional Training Course (GDPTC)
- (d) Graduate Diploma in Professional Examination (GDPE)

6. नीलांजन भारत का नागरिक है और योग्यता प्राप्त एडवोकेट है। वर्ष 2000 में वह उत्तर प्रदेश में जूडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ। किंतु, 2006 में उसने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। 2006 में उसने दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी और तब से वहीं काम कर रहा है। 2016 में नीलांजन किस पद पर नियुक्ति के योग्य होगा :

- (क) केवल हाईकोर्ट का न्यायाधीश
- (ख) हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का न्यायाधीश
- (ग) केवल जिला जज
- (घ) केवल सुप्रीम कोर्ट का जज



Nilanjan, is a citizen of India and a qualified Advocate. In the year 2000, he was appointed as a Judicial Magistrate in Uttar Pradesh. But in the year 2006, he resigned from the post of Judicial Magistrate. He started practising as an Advocate in Delhi High Court in the year, 2006 and since then he is practising as an advocate in Delhi High Court. In 2016, Nilanjan is eligible to be appointed as :

- (a) High Court Judge only
- (b) Both Supreme Court and High Court Judge
- (c) District Judge only
- (d) Supreme Court Judge only

7. 1940 में नवीन ने एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए. में सफलता प्राप्त की। वह भारत में एक 'प्लीडर' बनना चाहता था। उसे प्लीडरशिप की परीक्षा पास करनी थी जिसे एडवोकेट्स ऐक्ट 1961 के लागू होने से पहले \_\_\_\_\_ के द्वारा आयोजित किया जाता था। 1

(क) मेयर की कोर्ट

(ख) हाई कोर्ट

(ग) सुप्रीम कोर्ट

(घ) मोफुसिल कोर्ट

In the year 1940, Naveen passed B.A. course from a recognized University. He wanted to become a 'Pleader' in India. He was required to pass the 'Pleadership Examination' which was held by the \_\_\_\_\_ prior to the enactment of Advocates Act, 1961.

- (a) Mayor's Court
- (b) High Court
- (c) Supreme Court
- (d) Mofussil Court

8. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2005 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामलों में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पर घूस और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। लोकपाल - 1

- (क) पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध जाँच कर सकता है क्योंकि पूर्व-प्रधानमंत्री भी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2005 के सीमाक्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- (ख) पूर्व-प्रधानमंत्री के विरुद्ध जाँच नहीं कर सकता क्योंकि केवल विद्यमान प्रधानमंत्री ही लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता है।
- (ग) जाँच कर सकता है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के प्रावधानों के अनुसार पूर्व-प्रधानमंत्री के कार्य भी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2005 के अंतर्गत आएँगे।
- (घ) जाँच नहीं कर सकता क्योंकि पूर्व-प्रधानमंत्री का कथित आचरण अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2005 के सीमाक्षेत्र से बाहर है।

Allegations of bribery and corruption were made against the ex-prime minister of India, in matters pertaining to International relations under Lokpal and Lokayukta Act, 2005. The Lokpal :

- (a) can conduct inquiry against ex-prime minister as even ex-prime minister is within the purview of Lokpal and Lokayukta Act, 2005.
- (b) cannot conduct inquiry against ex-prime minister as only the conduct of acting prime minister is within the purview of Lokpal and Lokayukta Act, 2005.
- (c) can conduct inquiry as provisions of Article 105 of Indian Constitution will be applicable which will bring the conduct of ex-prime minister within the purview of Lokpal and Lokayukta Act, 2005.
- (d) cannot conduct inquiry as the alleged conduct of ex-prime minister is related to International Relations which is outside the purview of Lokpal and Lokayukta Act, 2005.

9. केन्द्र सरकार के कर्मचारी श्री लक्ष्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ हुई। अनुशासन समिति संस्तुत करती है कि श्री लक्ष्य को सेवाओं से बरखास्त कर दिया जाए और 3-12-2005 को सेवामुक्त करने का आदेश पारित करती है। अनुशासन समिति के द्वारा जाँच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति श्री लक्ष्य को नहीं दी गई। 2

क्या जाँच समिति की कार्यवाही न्यायोचित है? अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए।

Disciplinary Proceedings were started against Mr. Lakshay, a Central Government employee. The Disciplinary Committee recommends for dismissal of Mr. Lakshay from services and passes the dismissal order on 3-12-2005. The copy of the report of the inquiry of officer was not supplied to Mr. Lakshay by the disciplinary authority.

Whether the action of disciplinary authority is justified ? Give reason to your answer.

10. श्री स्वामी 1990 से दिल्ली उच्च न्यायालय तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं। उन्हें दीवानी तथा आपराधिक कानूनों की विशेष ज्ञान प्राप्त है। न्यायकक्ष में वे आमतौर पर काले-सफेद वस्त्र पहनकर आते हैं, गले में सफेद बैंड और कंधों पर फ्लैप्स वाला काला गाउन पहनते हैं। 18 नवंबर 2015 को श्री मेहता ने श्री स्वामी से सीधे संपर्क कर उन्हें जिला न्यायालय के एक निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील के लिए अपना एडवोकेट नियुक्त किया। श्री स्वामी ने अपने परामर्श शुल्क के रूप में एक लाख रुपए स्वीकार कर लिए अर्थात् अगले ही दिन से बिना समय बरबाद किए श्री स्वामी ने वकालत की रूपरेखा बनाना प्रारंभ कर दिया क्योंकि अपील करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2015 थी।

2

(क) श्री स्वामी एडवोकेट्स ऐक्ट 1961 के द्वारा मान्यताप्राप्त कानूनी प्रैक्टिशनरों की किस श्रेणी में आते हैं?

(ख) एडवोकेट्स ऐक्ट 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत क्या श्री स्वामी का आचरण उचित है? कारण सहित लिखिए।

Mr. Swami is a qualified Layer practising since 1990 in High Court of Delhi and in the Supreme Court of India. He is having special knowledge and expertise in the field of Civil and Criminal Laws. While appearing in a courtroom he usually dresses in black and white, wears a white band around his neck and a black gown having flaps on the shoulders. On 18 November 2015, Mr. Mehta directly approached and appointed Mr. Swami as his advocate, to file an appeal in the Delhi High Court against the decision of District Court. Mr. Swami accepted ₹ 1 lakh in cash as his consultation charges. On 19 November, 2015 i.e. on the very next day, without wasting any time Mr. Swami started drafting pleadings as 29 November, 2015 was the last day to file the appeal.

(a) Mr. Swami comes under which category of legal practitioner as recognized by the Advocates Act, 1961 ?

(b) Giving reason, state whether the conduct of Mr. Swami is justified as per the provisions of the Advocates Act, 1961 ?

11. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (Cr.PC) के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए क्या प्रावधान हैं? इन प्रावधानों द्वारा संचारित किन्हीं दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए। 2

What are the provisions of free legal aid available under Criminal Procedure Code (Cr.PC) in India ? State any two values communicated by these provisions.

12. एक अचल संपत्ति के अधिकार और कब्जे के बारे में श्रीमती उदिता और श्री भावेश के बीच एक विवाद था। विवाद के पक्षों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से श्री मोहन को एक निरपेक्ष तीसरे पक्ष के रूप में विवाद हल करने के लिए नियुक्त किया, श्री मोहन न केवल मध्यस्थ बने परन्तु उन्होंने पक्षों में संभावित समाधानों का सुझाव भी दिया ताकि उनके दावों और झगड़ों का हल निकल सके। 2

उपर्युक्त स्थिति में वैकल्पिक विवाद निपटान (ADR) के रूप में श्री मोहन की भूमिका का उल्लेख कीजिए।

There was a dispute between Ms. Udita and Mr. Bhavesh regarding title and possession of an immovable property. The parties to the dispute, out of their own free will appointed Mr. Mohan a neutral third party to resolve their dispute. Mr. Mohan acted not only as an interventionist but also suggested potential solutions to the parties, in order to resolve their claims and disputes.

State the role of Mr. Mohan as an Alternative Dispute Resolution (ADR) in the above given situation.

13. विधीक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1987 कैसे अस्तित्व में आया? 2

How did 'Legal Services Authorities Act, 1987' come into being ?

14. मेसर्स रोहताश ब्रदर्स एक भारतीय बॉडी कॉर्पोरेट तथा मेसर्स गैरी एंड फर्न ब्रदर्स, एक कनाडियन बॉडी कॉर्पोरेट के बीच समझौते की शर्तों के टूटने के बारे में एक विवाद है, दोनों कंपनियों ने अपने विवाद का निपटारा करने के लिए ज़रूरी कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए एक संस्था को नियुक्त किया, मध्यस्थता की कार्यवाही कनाडा में हुई और अधिनिर्णय भारत में लागू हुआ। 2

उपर्युक्त परिस्थिति में किन्हीं दो प्रकार की मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) की पहचान तथा व्याख्या कीजिए।

There is dispute between an M/S Rohtash Bros. an Indian Body Corporate and M/S Garry and Fern Bros. a Canadian Body Corporate, regarding breach of contractual terms. Both Companies appointed an institution for initiating the process required for settlement of their dispute. Arbitration proceedings were conducted in Canada and the award was enforced in India.

Identify and explain any two types of Arbitration mentioned in the above situation.

15. “भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्र पदस्थिति (स्टेटस) और उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं....।” 4

इस संदर्भ में उन विधिक प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए जो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को आदिष्ट (मैन्डेट) करते हैं। (कोई चार)

‘The independent status of the judiciary in India and the roles to be performed by it can be understood as two sides of the same coin....’ In this context, explain the legal provisions which mandate judge’s independence and impartiality. (Any four)

16. दो पड़ोसी देशों, आरुनलैंड और पोरेशिया के बीच विशेष आर्थिक क्षेत्र की हिस्सेदारी के बारे में एक संधि थी। इस बाध्यता की पूर्ति की कुछ शर्तों के बारे में दोनों देशों में एक विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं। आरुनलैंड ने संधि की बाध्यताओं को मानने से इनकार कर दिया। इससे पीड़ित पोरेशिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से परामर्श के लिए संपर्क किया। 4

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) अपने परामर्श दे सकता है? यदि हाँ तो, किस प्रावधान के अंतर्गत?

(ख) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के परामर्श देने के कार्यक्षेत्र का उल्लेख कीजिए।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा संप्रेषित किन्हीं दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए।

There was a treaty between two neighbouring countries namely Arunland and Poratia regarding sharing of special economic zone. A dispute arose between them regarding fulfilment of certain terms and conditions of this treaty obligation. Both the countries are not members of United Nations. Arunland refused to fulfil its treaty obligations. Aggrieved by this, Portia approached International Court of Justice (ICJ) for its advice.

- (a) Can International Court of Justice (ICJ) give its advisory opinions to the country? If yes, under which provision?
- (b) State the advisory jurisdiction of International Court of Justice (ICJ).
- (c) State any two values communicated by International Court of Justice.

17. केंद्र सरकार की कानूनी सहायता सेवा देने के उत्तरदायित्व के संदर्भ में :

4

(क) केंद्रीय अधिकरण की संरचना क्या है?

(ख) केंद्रीय अधिकरण के चार प्रकार्य लिखिए।

With regard to the responsibility of the Central Government to provide legal aid service :

(a) What is the composition of Central Authority ?

(b) State any four functions of the Central Authority.

18. बौद्धिक संपदा क्या है? बौद्धिक संपदा के किन्हीं तीन प्रकारों को स्पष्ट कीजिए।

4

What is Intellectual Property ? Explain any three types of Intellectual Property.

19. यूरोपीय महाद्वीप के एक देश में कानून और नियम बनाने का अधिकार केवल विधायिका को है। यहाँ न्यायाधीश को विशेष प्रकार के सबूत को प्रस्तुत करने की अनुमति है। न्यायाधीश की भूमिका सक्रिय है यहाँ तक कि उसे जाँच में भी सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति भी है।

4

(क) न्यायाधीश विवाचन (एडजूडिकेशन) की किस प्रणाली के अंतर्गत आता है?

(ख) यह देश किस न्याय प्रणाली का अनुगमन करता है?

(ग) ऊपर पहचान की गई विवाचन (एडजूडिकेशन) प्रणाली के एक लाभ और एक हानि का उल्लेख कीजिए।



In a Continental European Country, only the legislature has the power to create laws and rules. Here the judge is allowed to decide the presentation of specific form of evidence and the role of judge is active one in a way that he is even allowed to take active part in investigation.

- (a) To which system of adjudication does the judge belong to ?
- (b) State the type of jurisdiction followed in this country.
- (c) State any one advantage and any one disadvantage of the system of adjudication identified above.

20. भारतीय संविधान के खंड III में प्रदत्त 'मूल अधिकारों' के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 4

- (क) राज्य सरकार ने उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सार्वजनिक नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान किया जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व राज्य के अंतर्गत सेवाओं में नहीं हुआ है।
- (ख) दीपेंद्र एक रिक्शाचालक है और उसे एक सार्वजनिक रेस्तरां में प्रवेश नहीं करने दिया गया क्योंकि वह पिछड़े वर्ग से है।
- (ग) ग्राम पंचायत ने खुशी (18 वर्ष) तथा यश (20 वर्ष) के विवाह की अनुमति नहीं दी।
- (i) उपर्युक्त स्थितियों में से उसकी पहचान कीजिए जिसमें मूल अधिकारों के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है।
- (ii) भारतीय संविधान के खंड III में प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रावधानों के आलोक में प्रत्येक स्थिति का मूल्यांकन कीजिए और उस पर टिप्पणी कीजिए।

With regard to the provisions of 'Fundamental Rights' enshrined in Part III of the Indian Constitution, Consider the following situations and answer the questions that follow :

(a) State government gave reservations to Scheduled Castes, Scheduled Tribes in public employment, who have not been adequately represented in the services under the state.

(b) Dipender is a rickshaw puller and was not allowed to enter a public restaurant because he belonged to a backward class.

(c) Marriage of Khushi, aged 18 years and Yash, aged 20 years was disallowed by the village panchayat.

(i) Identify the situation from the given excerpts where a provision of fundamental rights has been violated.

(ii) In the light of the provisions for fundamental rights enshrined in part III of the Indian Constitution, Evaluate each situation and comment on it.

21. अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए किन्हीं दो कन्वेंशनों को समझाइए। 5

Explain any two conventions for promoting and protecting Human Rights in International sphere.

22. (क) टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में क्या सम्मिलित है ?

5

(ख) कारण देते हुए व्याख्या कीजिए कि क्या निम्नलिखित कार्य, 'असावधानी' के अंतर्गत आता है ?

केयरसेल टेलिकॉम के कर्मचारियों ने गली के एक मैनहोल को शाम के समय खोला और उसे खुला छोड़ दिया। उन्होंने उसे एक कैनवस से ढका पर उसे योंही छोड़ दिया। आठ साल का लड़का प्रिंस वहाँ खेल रहा था, वह इससे ठोकर खाकर मैनहोल में गिर गया। उसे चोटें लगीं।

(a) What Constitutes Tort of Negligence ?

(b) Explain with reasons whether the following act constitutes 'negligence'.

The employees of Care Cell Telecom opened a manhole in the street and in the evening left that manhole open. They covered it with canvas shelter, but left it unattended. Prince, 8 years old boy, who was playing there, stumbled over it and fell into the manhole and sustained injuries.

23. भारत और अमेरिका में विधि-शिक्षा (लीगल एजुकेशन) से संबंधित नियमों की तुलना कीजिए।

5

Compare the rules regarding Legal Education in India and the United States of America.

24. (क) भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकृत 'सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों' की व्याख्या कीजिए। 5

(ख) ऊपर स्पष्ट किए गए 'सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों' के आलोक में नीचे दी गई स्थितियों की समीक्षात्मक आकलन कीजिए।

(i) पंजाब में राजकीय सहायता प्राप्त एक विद्यालय ने रचित को प्रवेश देने से मना कर दिया क्योंकि उसकी मातृभाषा बंगला है और वह पंजाबी (गुरुमुखी) नहीं समझता।

(ii) वार्षिक बजट में शिक्षा के लिए सरकार ने सरकारी तथा राज्य द्वारा फंड दिए जाने वाले स्कूलों के लिए ₹ 36.5 करोड़ और ₹ 16.5 करोड़ धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों के लिए मंजूर किया।

(a) Explain the 'Cultural and Educational Rights' as granted by the Constitution of India.

(b) Critically assess the situations given below in the light of 'Cultural and Educational Rights' as explained above :

(i) A government aided school in Punjab denied admission to Rachit because his mother tongue is Bengali and he does not understand Punjabi (Gurumukhi).

(ii) In the annual budget for education the state government allocated ₹ 36.5 crores for government and state funded schools and ₹ 16.5 crores for schools run by religious minorities.

25. राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन और किन्हीं आठ प्रकार्यों को समझाइए। 6

Explain the constitution and any eight functions of National Commission of Women.

26. अपने पति की हत्या करने के लिए पलविंदर कौर को उनके पारिवारिक मित्र अरविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया। उसका पति शौकिया फोटोग्राफर था और फोटो डेवेलप करने के लिए कुछ वस्तु जो एक तात्कालिक विष था उसके पास होता था। एक दिन उसका पति बीमार था और वह उसके लिए कुछ दवा लाई। वह दवा डेवेलप करने वाले तरल पदार्थ के पास रख दी। उसके पति ने गलती से उसे पी लिया और मर गया। वह डर गई और अरविंदर सिंह की सहायता से उसने लाश को कुँए में डाल दिया। जब वह पुलिस कस्टडी में थी तो उसने महिला कांस्टेबल को पूरी कहानी बताई और घटना पर दुख व्यक्त किया। 6

(क) क्या पलविंदर कौर द्वारा दिया गया बयान अपराध स्वीकृति (कन्फेशन) या मानना (एडमिशन) है? कारण सहित उत्तर दीजिए।

(ख) स्वीकृति (एडमिशन) तथा अपराध स्वीकृति (कन्फेशन) में कोई चार अंतर लिखिए।

Palvinder Kaur was arrested for murder of her husband along with their family friend Arvinder Singh. Her husband was hobbyist photographer and used to keep handy photo developing material which is quick poison. One day, her husband was ill and she brought him some medicine. The medicine was kept near the liquid developer and her husband swallowed it by mistake and died. She got afraid and with the help of Arvinder Singh, she dumped the body in the well. When she was in Police custody, she told the whole story to one of the Lady Constables and expressed her grief over the matter.

(a) Will the statement given by Palvinder Kaur amounts to Confession or Admission ? Give reason for your answer.

(b) State any four differences between Admission and Confession.

27. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

6

(क) महिलाएँ और विधिक व्यवसाय

(ख) भारत में विधिवेत्ताओं के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित व्यावसायिक आचारशास्त्र (ईथिक्स)

Write short notes on the following :

(a) Women and the Legal Profession

(b) Professional Ethics for Lawyers in India, as laid down by Bar Council of India.

28. बेना बैंक में नूपुर का एक खाता था। उसने 28 जुलाई 2015 का पोटक बैंक के ए.टी.एम. (ATM) से ₹ 5,000 निकाले। मशीन से केवल ₹ 4,000 नकद ही निकले फिर भी उसके खाते से ₹ 5,000 निकाले दिखाए गए उसने तुरंत अपने बैंक अधिकारी से शिकायत की किंतु ₹ 1,000 अनेक शिकायतों के बाद भी खाते में क्रेडिट नहीं हुए।

6

(क) भारत में जाँच और हल के लिए बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े ओमबुड्समन की पहचान कीजिए।

(ख) क्या नूपुर उस ओमबुड्समन से संपर्क कर सकती है जिसका उल्लेख ऊपर खंड 'क' में है? कारण सहित उत्तर दीजिए।

(ग) यदि संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र की कार्य पद्धति को बुरी सेवा के बारे में किसी मामले से बचने के लिए एक ही की निगरानी में रखा जाना हो तो किस अधिकरण के पास ऐसे अधिकार हैं? उसके क्षेत्र और किए जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख कीजिए।

(घ) विवाद निपटान मैकेनिज़्म में ओमबुड्समन के होने का एक लाभ लिखिए।

Nupur maintained an account with Bena Bank. She withdrew an amount of ₹ 5,000 from the ATM of Potak bank on July 28, 2015. The cash dispensed by the machine was only ₹ 4,000. However, her account was debited by ₹ 5,000. She immediately lodged the complaint with her Bank officials but ₹ 1,000 was not credited back to her account even after repeated complaints.

- (a) Identify the Ombudsman within India to investigate and resolve complaints related to the banking sector.
- (b) Can Nupur approach this Ombudsman identified in part (a) above ? Give reason for your answer.
- (c) If the functioning of the entire banking sector is to be put under a vigil to avoid any issue of poor service, which institution has the authority to do so ? State the area activities to be performed by it.
- (d) State one advantage of the Ombudsman in the dispute resolution mechanism.

29. पहचानिए और स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित स्थितियों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस प्रकार का न्याय-क्षेत्राधिकार लागू किया जाएगा ? 6

- (क) नदी को साझा करने के बारे में भारत के दो राज्यों में विवाद हुआ।
- (ख) सार्वजनिक महत्व के किसी मामले को भारत के राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करते हैं।
- (ग) सर्वोच्च न्यायालय में श्री राजन के द्वारा एक दीवानी अपील दायर की गई जिसके लिए हाईकोर्ट द्वारा सर्टीफिकेट ऑफ अपील स्वीकार नहीं किया गया था।

Identify and explain which type of jurisdiction will be applied by the Supreme Court of India under the following given situations :

- (a) A dispute arose between two states in India regarding sharing of river.
- (b) President of India refers a matter of public importance to the Supreme Court of India.
- (c) A civil appeal was filed by Mr. Rajan in the Supreme Court of India for which certificate of appeal was not granted by the High Court.

**30.** नेशनल लीगल सर्विसेज आथॉरिटी, 2010 के प्रमुख लक्षणों के बारे में विस्तार से लिखिए।

**6**

Write in detail, broad features of National Legal Services Authority Regulations, 2010.